माननीय एम. आर. अग्निहोत्री के समक्ष,जे.

पंजाब राज्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और यू. टी. चंडीगढ़ और अन्य,-प्रतिवादी।

1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 4441।

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 226-कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 19,1952 का अधिनियम 1988 के अधिनियम 33 तक संशोधित)-धारा 1-ए-याचिकाकर्ता नियोक्ता जो 200 श्रमिकों को रोजगार देते हुए हाइडल चैनल के निर्माण और निर्माण गतिविधि में लगे हुए हैं-पहले भविष्य निधि में योगदान के रूप मे वेतन से कटौती करने का निर्णय लिया-इसके बाद अवसर प्रदान किए बिना भविष्य निधि में योगदान के रूप में वेतन में कटौती करने के निर्णय को उलट दिया-याचिकाकर्ता को उद्योग मानने वाले और योगदान जारी रखने के लिए उत्तरदायी प्रतिवादी के निर्णय को चुनौती दी गई-प्रतिवादी के इस निर्णय को सही ठहराया।

अभिनिर्धारित किया गया कि इस अधिसूचना के आधार पर, याचिकाकर्ता-नियोक्ता मार्च से 'अधिनियम' के उद्देश्यों के लिए 'उद्योग' की परिभाषा में आता है, और इसी आधार पर याचिकाकर्ता-नियोक्ता ने कटौती करना शुरू कर दिया था। इस आधार पर की गई कटौती को बंद करने का विवादित निर्णय न केवल मनमाना और एकपक्षीय था, बल्कि पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर था।इसके परिणामस्वरूप गरीब श्रमिकों को काफी वित्तीय नुकसान हुआ है, जिन्हें अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी में घसीटा गया है, विशेष रूप से जब

कर्मचारी और नियोक्ता के बीच लड़ाई सबसे असमान है, क्योंकि कर्मचारी राज्य के संसाधनों की बराबरी नहीं कर सकता है।

(पैरा 4)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय निम्नलिखित जारी करने की कृपा करे: —

(क) 'पी-वी' आदेश को निरस्त करते हुए उत्प्रेषण का एक रिट,

(ख) मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त कोई अन्य आदेश, रिट या निर्देश;

आगे प्रार्थना की जाती है कि:—

(1) आदेश 'पी-1' की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से छूट दी जा सकती है।

((घ) प्रतिवादी को अग्रिम सूचना जारी करने से छूट दी जा सकती है;

(हाय) आदेश 'पी-1' के कार्यान्वयन/अनुपालन पर वर्तमान रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान रोक लग सकती है।

एस. के. भाटिया, डी. ए. जी (पंजाब), याचिकाकर्ता के लिए।

एस. डी. शर्मा, दिवाहर पाठक के साथ अधिवक्ता, सी. एल. चौधरी और जी. एस. चड्ढा, प्रतिवादीओं के लिए प्रतिवादी संख्या 2 से 118 तक के अधिवक्ता

निर्णय

एम.आर अग्निहोत्री, जे।

(1) पंजाब राज्य ने कार्यकारी अभियंता, मुकेरियन हाइडल सिविल निर्माण प्रभाग संख्या 1 (आई. पी. पी. प्रभाग), तलवाड़ा टाउनशिप द्वारा से, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या 19) की खंड 7-ए के तहत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के 6 मई, 1987 के आदेश को रद्द करने के लिए इस अदालत के रिट क्षेत्राधिकार को लागू किया है, जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जायेगा, जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "अधिनियम" के प्रावधान मुकेरियन हाइडल सिविल निर्माण प्रभाग संख्या 1, तलवाड़ा टाउनशिप के कर्मचारियों पर लागू थे और नियोक्ता प्रतिष्ठान कानून के अनुसार अपने कर्मचारियों-प्रतिवादियों संख्या 2 से 118 के भविष्य निधि के लिए अपना योगदान नियमित रूप से जमा करने के लिए बाध्य था।क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के विवादित आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता का प्रमुख आधार यह है कि याचिकाकर्ता प्रतिष्ठान 'अधिनियम' की खंड 2 (i) के तहत 'उद्योग' शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं था, क्योंकि यह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की खंड 2 (j) के तहत परिकल्पित 'उद्योग' की

परिभाषा से अलग था।

(2) याचिकाकर्ता द्वारा की गई याचिका का विस्तार करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार का सिंचाई विभाग औद्योगिक विवाद अधिनियम के उद्देश्यों के लिए "उद्योग" की परिभाषा के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन यह "अधिनियम" के उद्देश्यों के लिए शामिल नहीं है क्योंकि यह एक कारखाना नहीं है।यह उस आधार पर था कि अनजाने में, याचिकाकर्ता-नियोक्ता ने मार्च, 1983 से प्रभावी कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान के कारण अपने कर्मचारियों के वेतन से, यानी प्रतिवादी संख्या 2 से 118 तक की कटौती करना शुरू कर दिया और ऐसा करना जून, 1984 तक जारी रखा। इसके बाद, जब याचिकाकर्ता-नियोक्ता को एहसास हुआ कि यह 'अधिनियम' के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं है, तो उसने कोई भी कटौती करना [बंद] कर दिया।

(3) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दायर लिखित बयान में, एक विस्तृत संस्करण में यह खुलासा किया गया है कि याचिकाकर्ता-नियोक्ता का मुकेरियन हाइडल सिविल निर्माण प्रभाग, हाइडल चैनल के संबंध में लगभग 200 श्रमिकों को नियुक्त करके निर्माण और निर्माण गतिविधि में लगा हुआ है, जिनमें से सभी कार्य-प्रभारित आधार पर नहीं हैं, इसके अलावा, कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को 'अधिनियम' की खंड 2 (एफ) के तहत रोजगार की परिभाषा के तहत शामिल किया गया था, क्योंकि वे प्रतिष्ठान के काम, हाइडल चैनल के निर्माण और उसके रखरखाव आदि के संबंध में कार्यरत थे।

(4) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों को देखने के बाद, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता नियोक्ता, अर्थात मुखेरियन हाइडल सिविल निर्माण प्रभाग 'अधिनियम' के उद्देश्यों के लिए 'उद्योग' की परिभाषा के अंतर्गत आता है और इसने भविष्य निधि में उनके योगदान द्वारा से श्रमिकों के वेतन से कटौती करने के लिए पहले ही सही निर्णय लिया है।सबसे पहले, एक बार कर्मचारियों के लाभ के लिए निर्णय लेने के बाद, उन्हें सुनने का अवसर दिए बिना इसे वापस नहीं लिया जा सकता था।ऐसा नहीं किए जाने के कारण, याचिकाकर्ता-नियोक्ता को कानूनी रूप से अपने पहले के निर्णय को उलटने और उपरोक्त कटौती को रोकने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि यह कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन था जो उनके हित के लिए प्रतिकूल और अपायकर था। इसके अलावा, 'अधिनियम' की खंड 1 (3) (बी) के अनुसार, बीस से अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को 23 सितंबर, 1980 को जारी निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा 'अधिनियम' के उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से शामिल किया गया था:-

श्रम मंत्रालय,

नई दिल्ली, 23 सितंबर, 1980

जीएसआर 1069.—कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम (1952 का 19) की धारा 1 की उप-धारा (3) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निर्दिष्ट करता है कि भवन और निर्माण उद्योग में लगे प्रत्येक प्रतिष्ठान और जिनमें से प्रत्येक में बीस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, को प्रतिष्ठानों के एक खंड के रूप में निर्धारित करती है, जिन पर उक्त अधिनियम के प्रावधान 31 अक्टूबर से लागू होंगे।

इस अधिसूचना के आधार पर, याचिकाकर्ता-नियोक्ता को 'अधिनियम' के उद्देश्यों के लिए 'उद्योग' की परिभाषा में मार्च से शामिल किया गया है और इसी

आधार पर, याचिकाकर्ता नियोक्ता ने कटौती करना शुरू कर दिया था।इसके बाद की गई कटौती को बंद करने का विवादित निर्णय न केवल मनमाना और एकपक्षीय था, बल्कि पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर था।इसके परिणामस्वरूप गरीब श्रमिकों को काफी वित्तीय नुकसान हुआ है, जिन्हें अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी में घसीटा गया है, विशेष रूप से जब कर्मचारी और नियोक्ता के बीच लड़ाई सबसे असमान है, क्योंकि कर्मचारी राज्य के संसाधनों की बराबरी नहीं कर सकता है।

(1) इन विचारों को ध्यान में रखते हुए और श्रमिकों को सक्षम रूप से मुआवजा देने के लिए, मैंने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, प्रतिवादी संख्या 1, के दिनांक 6 मई, 1987 के आदेश को बरकरार रखा और लागत के साथ रिट याचिका को खारिज कर दिया, जो रु 1000 प्रत्येक प्रतिवादी-कर्मचारी को दिए जायेंगे ।याचिकाकर्ता नियोक्ता को जुलाई, 1984 से आज तक प्रत्येक प्रतिवादी-कर्मचारी के भविष्य निधि योगदान को जमा करने का निर्देश दिया जाता है, और ऐसा करते समय, कर्मचारी के पक्ष में दी गई लागत की राशि को समायोजित करें।

जे एस टी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशिमा गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम,

हरियाणा